राजस्थान एसआरटीसी एवं अन्य

बनाम

मोहार सिंह

(सिविल अपील संख्या 2945/2008)

24 अप्रैल 2008

[एस.बी. सिन्हा और पी.पी. नाओलेकर, न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 9:

सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार – कार्य–क्षेत्र और दायरा – सेवा/श्रम मामलों के संबंध में – नियोक्ता–निगम एक क़ानून के तहत बनाया गया – कर्मचारी की बर्खास्तगी – उसने इसे चुनौती देते हुए सिविल मुकदमा दायर किया – नियोक्ता द्वारा विवाद उठाया गया कि सिविल न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था – अभिनिर्धारित: सिविल न्यायालयों के पास उन सिविल मुकदमों को छोड़कर, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है, सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है – यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम या सहयोगी कानूनों के तहत किसी अधिकार का दावा किया जाता है, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं किया जाता है, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा – तथ्यों पर, नियोक्ता–निगम, संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है – यदि उसकी ओर से की गई कार्रवाई, संवैधानिक प्रावधानों या क़ानून या वैधानिक नियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है, तो सिविल न्यायालय के पास संबंधित कर्मचारी को पूर्ण वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है – भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 12 और 14 – औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 – सड़क निगम अधिनियम, 1951।

प्रथम अपीलकर्ता, सड़क निगम अधिनियम, 1951 के तहत गठित और निगमित, एक वैधानिक निगम है। प्रत्यर्थी, निगम द्वारा नियोजित बस के चालक ने कथित तौर पर कदाचार किया। अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और प्रत्यर्थी को दोषी पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा की गई अपील, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई थी।

प्रत्यर्थी ने बर्खास्तगी के आदेश के साथ–साथ अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए सिविल मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमे पर फैसला सुनाया कि उसके समक्ष दिए गए आदेश अवैध थे, कानून की नजर में खराब थे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थे। सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश को, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ने बरकरार रखा।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सिविल न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1. धारा 9, सीपीसी में प्रावधान है कि सभी सिविल न्यायालयों को उन मुकदमों को छोड़कर, जिनमें उनका संज्ञान स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की

सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा। सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है।

1.2. सिविल न्यायालय के पास सेवा मामलों में सीमित क्षेत्राधिकार हो सकता है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। यह अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित आदेश या लगाए गए दंड की मात्रा पर अपील करने का हकदार नहीं हो सकता है। किसी दिए गए मामले में यह विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(बी) को ध्यान में रखते हुए सेवा में बहाली का निर्देश नहीं दे सकता है, लेकिन, जहां वादी द्वारा सामान्य कानून के संदर्भ में या किसी अन्य क़ानून के तहत अधिकार का दावा किया गया है जिसने पहली बार एक नया अधिकार बनाया है और जब उक्त अधिकार को लागू करने के लिए एक मंच भी बनाया गया है, तो सिविल न्यायालय के पास उस मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र भी होगा जहां वादी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार या सेवा के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले क़ानून या वैधानिक नियमों के अनिवार्य प्रावधानों के लाभ का दावा करता है।

1.3. सड़क निगम अधिनियम, 1951 के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय आमतौर पर मुकदमे का विषय होगा। हालाँकि, सिविल न्यायालय एक सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। हालाँकि, यदि संबंधित कर्मचारी 1947 अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक 'कर्मचारी' है, तो वह सामान्य कानून उपायों के अलावा, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है। जब कोई अधिकार आम कानून के अधिकार की तुलना में दो क़ानूनों के तहत अर्जित होता है, तो संबंधित कर्मचारी के पास अपना मंच चुनने का विकल्प होगा। इसके अलावा, उस अधिकार के बीच एक अंतर है जो किसी नियोक्ता को पहली बार किसी क़ानून के तहत प्रदान किया जाता है और एक उपाय भी प्रदान करता है और जो सामान्य कानून अधिकार के तहत मामलों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। केवल पूर्व के मामले में, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को आवश्यक निहितार्थ द्वारा वर्जित माना जा सकता है। न्यायालय आमतौर पर ऐसी व्याख्या नहीं अपनाते हैं जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीन लेती है।

1.4. यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम या सहयोगी कानूनों के तहत किसी अधिकार का दावा किया जाता है, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित होगा, लेकिन यदि ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं किया जाता है, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

1.5. अपीलकर्ता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में, एक 'राज्य' है। इसे एक क़ानून के तहत बनाया गया है। एक राज्य के रूप में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं के साथ–साथ संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। यह क़ानून के अनिवार्य प्रावधानों या इसके द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी बाध्य है। ऐसी स्थिति में, अगर यह पाया जाता है कि राज्य की ओर से की गई कार्रवाई, संवैधानिक प्रावधानों या क़ानून या वैधानिक नियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन है, तो सिविल न्यायालय के पास पूर्ण वेतन के साथ, बहाली का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र होगा।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके और अन्य एआईआर (1975) एससी 2238 – पर निर्भर।

राजस्थान राज्य रोडवेज परिवहन निगम एवं अन्य बनाम कृष्ण कांत और अन्य (1995) 5 एससीसी 75; *राजस्थान एसआरटीसी एवं अन्य बनाम खादरमल*, (2006) 1 एससीसी 59; *राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम जाकिर हुसैन* (2005) 7 एससीसी 447; *यूपी राज्य बनाम शत्रुघ्न लाल*

और अन्य **एआईआर (1998) एससी 3038 और** *प्रागा टूल्स निगम बनाम सी. वी. इमानुअल और अन्य* **एआईआर (1969) एससी 1306 – संदर्भित।**

वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वॉटरवर्क्स कंपनी बनाम हॉक्सफ़ोर्ड **(1859) 6 सीबी (एनएस) 336– संदर्भित।**

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा *वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (11 वां संस्करण)***– *संदर्भित।***

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2945/2008

एस.बी.सी.एस.ए संख्या 330/2000 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के दिनांक 23.11.2005 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से एच.डी. थानवी, अफचना मिश्रा और सुशील कुमार जैन।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया,

न्यायाधीश एस.बी. सिन्हा, द्वारा– 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. प्रथम अपीलकर्ता (निगम) एक वैधानिक निगम है जो सड़क निगम अधिनियम, 1951 के तहत गठित और निगमित है। यहां प्रत्यर्थी, निगम द्वारा नियोजित एक बस का चालक था।

3. प्रत्यर्थी की ओर से कथित कदाचार के आरोप में, उसके खिलाफ 6.11.1982 को या उसके आसपास अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। जांच अधिकारी ने उसे उक्त आरोप में दोषी पाया। दिनांक 31.5.1985 के एक आदेश के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सेवाओं से बर्खास्त करने की सजा दी। इसके अलावा यह निर्देश दिया गया कि वह निर्वाह भत्ते के रूप में उसे पहले से ही भुगतान की गई राशि को छोड़कर आगे की मजदूरी का हकदार नहीं होगा।

4. उनके द्वारा की गई अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 16.6.1987 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

5. प्रत्यर्थी ने न्यायालय अतिरिक्त मुंसिफ, जयपुर में एक सिविल मुकदमा दायर किया जिसे सिविल मुकदमा संख्या 632/88 (290/86) के रूप में चिह्नित किया गया था। अपने लिखित बयान में, अपीलकर्ता ने, अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया कि सिविल न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। सिविल न्यायालय द्वारा तय किए गए कुछ मुद्दे थे:

> "(1) क्या बर्खास्तगी आदेश संख्या 1516 दिनांक 31.5.1985 और अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दिनांक 16.6.1987 कानूनन अवैध हैं?
>
> xxx xxx xx
>
> (3) क्या न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? "

6. मुद्दे संख्या 1 का निर्धारण करते समय, ट्रायल न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह माना कि समाप्ति का आदेश दिनांक 31.5.1985 और साथ ही अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अवैध, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था, यह कहते हुए:

i. आरोप–पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़, जिस पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया था, प्रत्यर्थी को प्रदान नहीं किए गए थे;

ii. उन्हें विभाग की ओर से जांचे गए गवाहों से जिरह करने की अनुमति नहीं थी; और
iii. जांच अधिकारी ने अभियोजक की तरह काम किया।

7. उक्त निष्कर्षों पर, मुक़दमे का फैसला यह कहते हुए सुनाया गया:

> "परिणामस्वरूप, यह आदेश दिया जाता है कि वादी के मुकदमे को, प्रत्यर्थी के खिलाफ हुक्मनामित किया जाता है, यह घोषित करते हुए कि प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश संख्या 1516 दिनांक 31.5.1985 और अपीलकर्ता प्राधिकरण के आदेश दिनांक 16.6.1987 को अवैध, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। यह भी घोषित किया जाता है कि वादी को बिना किसी रुकावट के प्रत्यर्थी की निरंतर सेवा में माना जाएगा और वह सभी मौद्रिक लाभ प्राप्त करने का भी हकदार होगा। यदि वह निरंतर सेवा में रहा होता तो वह इसका हकदार होता।"

8. अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध की गई अपील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर शहर द्वारा दिनांक 5.5.2000 के एक निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा दायर दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठता है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री थानवी यह प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सिविल न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

यह बताया गया कि चूंकि *राजस्थान राज्य रोडवेज परिवहन निगम और अन्य बनाम कृष्णकांत और अन्य* [(1995) 5 एससीसी 75) और *राजस्थान एसआरटीसी और अन्य बनाम खदरमल* [(2006) 1 एससीसी 59], 2005 की सिविल अपील संख्या 3428 में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।

10. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में प्रावधान है कि सभी सिविल न्यायालयों को उन मुकदमों को छोड़कर, जिनमें उनका संज्ञान स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है।

हमारे विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या यह आवश्यक निहितार्थ से वर्जित है।

11. सिविल न्यायालय के पास सेवा मामलों में सीमित क्षेत्राधिकार हो सकता है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। यह अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित आदेश या लगाए गए दंड की मात्रा पर अपील करने का हकदार नहीं हो सकता है। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(बी) को ध्यान में रखते हुए यह किसी दिए गए मामले में सेवा में सीधे बहाली नहीं कर सकता है, लेकिन, यह एक घिसा–पिटा कानून है कि जहां वादी द्वारा सामान्य कानून के संदर्भ में अधिकार का दावा किया जाता है या उस कानून के अलावा किसी अन्य कानून के तहत जिसने पहली बार एक नया अधिकार बनाया है और जब उक्त अधिकार को लागू करने के लिए एक मंच भी बनाया गया है, तो सिविल न्यायालय के पास उस मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र भी होगा जहां वादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार या सेवा के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले क़ानून या वैधानिक नियमों के अनिवार्य प्रावधानों के लाभ का दावा करता है।

12. औद्योगिक कानून के तहत, और विशेष रूप से 1947 अधिनियम के तहत, उपयुक्त सरकारों और औद्योगिक न्यायालयों सहित उसमें निर्दिष्ट प्राधिकारियों को विभिन्न कार्य करने होते हैं। इसके अंतर्गत, नियम एवं शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। नियोक्ता के हाथों, सेवा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन भी न्यायसंगत है। यह देखने के लिए अधिनियम के तहत सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं कि श्रमिकों की सेवाओं को अन्यायपूर्ण तरीके से समाप्त नहीं किया जाए। 1947 का अधिनियम 'सेवा समाप्ति' की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है। इसके तहत सेवा समाप्ति की पूर्ववर्ती शर्तें प्रदान की गई हैं।

1951 अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय आमतौर पर मुकदमे का विषय होगा। हालाँकि, सिविल न्यायालय, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, एक सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। हालाँकि, यदि संबंधित कर्मचारी 1947 अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक 'कर्मचारी' है, तो वह सामान्य कानून उपायों के अलावा, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है।

जब कोई अधिकार आम कानून के अधिकार की तुलना में दो क़ानूनों के तहत अर्जित होता है, तो संबंधित कर्मचारी के पास अपना मंच चुनने का विकल्प होगा।

13. हमें उस अधिकार के बीच अंतर पर भी ध्यान देना चाहिए जो किसी नियोक्ता को पहली बार किसी क़ानून के तहत प्रदान किया जाता है और एक उपाय भी प्रदान करता है और जो सामान्य कानून अधिकार के तहत मामलों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। केवल पूर्व के मामले में, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को आवश्यक निहितार्थ द्वारा वर्जित माना जा सकता है।

यह प्रश्न *प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके और अन्य* [एआईआर 1975 एससी 2238] मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। जैसा कि यहां पहले देखा गया था, वैसा ही अंतर इसमें देखा गया। न्यायालय ने *वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वेट वर्क्स कंपनी बनाम हॉक्सफ़ोर्ड* [(1859) 6 सीबी (एनएस) 336] को, इस प्रकार उद्धृत किया:

> "मामलों की तीन श्रेणियां हैं जिनमें क़ानून द्वारा एक दायित्व स्थापित किया जा सकता है। एक ऐसा वर्ग है जहां सामान्य कानून में एक दायित्व विद्यमान है, और जिसे क़ानून द्वारा केवल एक विशेष प्रकार के उपचार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है; वहां, जब तक कि क़ानून में आवश्यक रूप से सामान्य कानून उपचार को छोड़कर शब्द शामिल हैं, वादी के पास या तो क़ानून के तहत या सामान्य कानून के तहत आगे बढ़ने का चुनाव है। फिर एक दूसरा वर्ग है, जिसमें वे मामले शामिल हैं जिनमें एक क़ानून ने एक दायित्व बनाया है, लेकिन है इसके लिए कोई विशेष उपाय नहीं दिया गया है; वहां पक्ष इसे लागू करने के लिए सामान्य कानून में ऋण या अन्य उपाय की कार्रवाई अपना सकती है। तीसरा वर्ग वह है जहां क़ानून एक दायित्व बनाता है जो सामान्य कानून में मौजूद नहीं है, और इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय भी देता है यह– "उस वर्ग के संबंध में यह हमेशा माना गया है कि पक्ष को क़ानून द्वारा दिए गए उपाय को अपनाना चाहिए।"

निर्णयों के अन्य अनुपात का विश्लेषण करने के बाद, इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया:

> 'संक्षेप में, औद्योगिक विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर लागू सिद्धांतों को इस प्रकार कहा जा सकता है:
>
> 1) यदि विवाद कोई औद्योगिक विवाद नहीं है, न ही यह अधिनियम के तहत किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है और इसका समाधान केवल सिविल न्यायालय में है।

2) यदि विवाद, एक औद्योगिक विवाद है जो सामान्य या आम कानून के तहत अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है और अधिनियम के तहत नहीं, तो सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वैकल्पिक है और इसे राहत के लिए अपना उपाय चुनने के लिए संबंधित वादकर्ता के चुनाव पर छोड़ दिया जाता है जो किसी विशेष उपाय में दिए जाने के लिए सक्षम है।
3) यदि औद्योगिक विवाद, अधिनियम के तहत बनाए गए किसी अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित है, तो मुकदमा करने वाले के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय, अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकारन प्राप्त करना है।
4) यदि जिस अधिकार को लागू करने की मांग की जा रही है, वह अध्याय V ए जैसे अधिनियम के तहत बनाया गया अधिकार है, तो इसके प्रवर्तन का उपाय या तो धारा 33 सी है या औद्योगिक विवाद उठाना, जैसा भी मामला हो।"

14. हमारी राय में, उक्त सिद्धांत को इस प्रकृति के मामले में लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय आमतौर पर ऐसी व्याख्या नहीं अपनाते जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीन लेती हो।

15. हम इस संबंध में न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा लिखित वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों (11 वें संस्करण) के निम्नलिखित अंशों पर लाभकारी रूप से ध्यान दे सकते हैं:

> "यह एक सिद्धांत है जिसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है और इसे "मौलिक नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है। इस नियम के एक आवश्यक परिणाम के रूप में सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रावधानों और सिविल अदालतों के अलावा अन्य प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाता है। नागरिक अदालतों में नागरिक प्रकृति के प्रश्नों पर निर्णय लेने के क्षेत्राधिकार का अस्तित्व एक सामान्य नियम है और बहिष्करण एक अपवाद है, यह दिखाने के लिए सबूत का बोझ कि किसी विशेष मामले में क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है, इस तरह का विवाद उठाने वाले पक्ष पर है। यह नियम कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, इस सिद्धांत पर आधारित है कि सिविल कोर्ट, सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालतें हैं और लोगों को अधिकार है, जब तक कि स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से राज्य के सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालतों तक मुफ्त पहुंच के लिए जोर देने से प्रतिबंधित न किया गया हो। दरअसल, यह सिद्धांत केवल सिविल अदालतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपराधिक अदालतों सहित सामान्य क्षेत्राधिकार की सभी अदालतों पर लागू होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालतों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर प्रावधानों के सख्त निर्माण से संबंधित नियम को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया था।"

16. *कृष्ण कांत (*पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने राय दी कि जहां किसी विवाद में नौकर की मान्यता और औद्योगिक विवाद अधिनियम और/या इसके सहयोगी अधिनियम जैसे औद्योगिक कर्मचारी (स्थायी आदेश) अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकारों और दायित्वों का प्रवर्तन शामिल है, न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। *प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स* (पूर्वोक्त) को यह कहते हुए समझाया गया:

> "25. यह सिद्धांत संख्या 2 है, और विशेष रूप से परिच्छेद 24 में दिए गए योग्य कथन, जिसने विवाद को जन्म दिया है। सिद्धांत संख्या 2 के अनुसार, यदि विवाद सामान्य या सामान्य कानून के तहत किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न औद्योगिक विवाद है, न कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वैकल्पिक है और यह संबंधित व्यक्ति पर छोड़ दिया गया

है कि वह सिविल न्यायालय का रुख करे या औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा प्रदान की गई मशीनरी का सहारा ले। लेकिन सिद्धांत संख्या 2 अकेला नहीं है; यह परिच्छेद 24 द्वारा योग्य है। अब प्रस्तर 24 क्या कहता है? यह कहता है कि (i) औद्योगिक विवाद अधिनियम में "औद्योगिक विवाद" की परिभाषा के मद्देनजर, सामान्य या सामान्य कानून के तहत विशेष रूप से किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होने वाला कोई औद्योगिक विवाद नहीं होगा। अधिकांश औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होने वाले विवाद होंगे। (ii) एक गैर–प्रायोजित श्रमिक की बर्खास्तगी एक व्यक्तिगत विवाद है, न कि औद्योगिक विवाद (बेशक, यह कामगारों के संघ या कामगारों के निकाय द्वारा समर्थित नहीं है), लेकिन धारा 2–ए ने इसे एक औद्योगिक विवाद बना दिया है। इसके कारण, सिविल अदालतों के पास सिद्धांत संख्या 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों से निपटने का शायद ही कोई अवसर होगा। कुल मिलाकर, औद्योगिक विवाद, सिद्धांत संख्या 3 के अंतर्गत आने के लिए बाध्य हैं। (सिद्धांत संख्या 3 कहता है कि विवाद कहां से संबंधित है अधिनियम द्वारा बनाए गए अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए, एकमात्र उपाय अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकारन प्राप्त करना है।)"

हालाँकि, उस मामले में, इस न्यायालय ने उस डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया जो अपील का विषय था।

17. हम यहां ऐसी स्थिति से चिंतित नहीं हैं क्योंकि वादी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या औद्योगिक कर्मचारी (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत उत्पन्न होने वाले अधिकार के आधार पर इसका दावा नहीं किया जा रहा है।

हम यह भी देख सकते हैं कि *राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम जाकिर हुसैन* [(2005) 7 एससीसी 447] में, जिस पर विद्वान वकील ने भी जवाब दिया, इस न्यायालय ने *कृष्ण कांत* (पूर्वोक्त) पर ध्यान दिया, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निर्णय के अनुच्छेद 32 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि समाप्ति संबंधित कर्मचारी का मामला सरल था और इसमें कोई कलंक नहीं था और इस प्रकार, किसी भी कदाचार के आधार पर कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने से पहले कानून को किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं होती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि प्रबंधन परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने का पूरी तरह से हकदार था, अगर उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं।

18. हालाँकि, *यूपी राज्य बनाम शत्रुघ्न लाल और अन्य* [एआईआर 1998 एससी 3038] में इस न्यायालय ने कहा कि जहां गवाहों के बयान की प्रतियां अपराधी कर्मचारी को प्रदान नहीं की गईं, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा:

> "यह भी पाया गया है कि प्रारंभिक जांच के दौरान, प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ कई गवाहों की जांच की गई थी, और यह सही भी है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में अपराधी जुड़े नहीं थे, और उसके बाद आरोप पत्र तैयार किया गया था। उन बयानों की प्रतियां, हालांकि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई थीं, उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गईं। चूंकि इस संबंध में अपीलकर्ता की ओर से भी विफलता थी, इसलिए अधिकरण का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन किया गया और प्रत्यर्थी को सुनवाई का प्रभावी अवसर नहीं दिया गया, विशेष रूप से अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज किए गए

बयानों की प्रतियों की आपूर्ति न करने से प्रत्यर्थी को अपना बचाव करने में कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ।"

19. *खादरमल* (पूर्वोक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और जो आदेश पारित किए गए थे उनमें कानून का कोई बल नहीं था। जाहिर है, इस न्यायालय ने 2005 के सिविल अपील संख्या 3428 (पूर्वोक्त) में उक्त निर्णय में *कृष्ण कांत* (पूर्वोक्त) और *खादरमल* (पूर्वोक्त) के बीच स्पष्ट विरोधाभास पाया।

हालाँकि, *खादरमल* (पूर्वोक्त) में भी, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि कोई पिछला वेतन भुगतान किया गया है, तो उसे वसूल नहीं किया जाएगा।

20. यहां पहले उल्लिखित निर्णय स्पष्ट रूप से एक अंतर लाते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम या सहयोगी कानूनों के तहत किसी अधिकार का दावा किया जाता है, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं किया जाता है, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

21. अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है। इसे एक क़ानून के तहत बनाया गया है। एक राज्य के रूप में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं के साथ–साथ संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। यह क़ानून के अनिवार्य प्रावधानों या इसके द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य है।

22. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी बाध्य है। ऐसी स्थिति में, यह पाया जाता है कि राज्य की ओर से की गई कार्रवाई संवैधानिक प्रावधानों या क़ानून या वैधानिक नियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन है, सिविल न्यायालय के पास पूर्ण वेतन के साथ बहाली का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र होगा।

23. *प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम सी वी इमैनुअल और अन्य* [एआईआर 1969 एससी 1306] में, यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> "इसलिए, परमादेश के मुद्दे के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि इसमें दावा करने वाले के लिए कानूनी कर्तव्य के प्रदर्शन का कानूनी अधिकार है जिसके खिलाफ यह मांगा गया है। परमादेश का एक आदेश, एक व्यक्ति, निगम या एक अवर न्यायाधिकरण को निर्देशित एक आदेश है, जिसमें उनसे निर्दिष्ट एक विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है जो उनके कार्यालय से संबंधित है और एक सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति या प्राधिकारी पर वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है वह एक सार्वजनिक अधिकारी या आधिकारिक निकाय हो। उदाहरण के लिए, किसी संस्था के किसी अधिकारी को उस क़ानून की शर्तों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए एक परमादेश जारी किया जा सकता है जिसके तहत या जिसके द्वारा संस्था का गठन या शासित किया जाता है और साथ ही कंपनियों या निगमों को उनके उपक्रमों को अधिकृत करने वाले क़ानून द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सार्वजनिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए एक क़ानून द्वारा गठित कंपनी के ख़िलाफ़ भी एक परमादेश होगा।"

24. उपरोक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। चूंकि प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

बी.बी.बी. अपील खारिज।

विक्रांत ठाकुर की देखरेख में सुमीत कपूर द्वारा अनुवादित।